

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:- रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्या:-163/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/163)

1. श्रीमती नन्दू पत्नि देवीलाल, जाति गर्जर, निवासी ग्राम-चावण्डिया, ग्रामपंचायत सतावडिया, तहसील मसूदा जिला ब्यावर।
2. श्री दूदा पुत्र देवीलाल जाति गर्जर, निवासी ग्राम चावण्डिया ग्रामपंचायत सतावडिया, तहसील मसूदा जिला ब्यावर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्री भैरू पुत्र श्री लादू जाति गर्जर, निवासी ग्राम चावण्डिया ग्रामपंचायत सतावडिया, तहसील मसूदा जिला ब्यावर।
2. श्री मादू पुत्र देवीलाल जाति गर्जर, निवासी ग्राम चावण्डिया ग्रामपंचायत सतावडिया, तहसील मसूदा जिला ब्यावर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मसूदा जिला ब्यावर।
4. उप-पंजीयक, मसूदा तहसील जिला ब्यावर।

रेस्पोडेंटस



अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 03.04.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा राजस्व वाद संख्या 174/2023 (2023/389)

उपस्थित:-

1. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शंकरलाल चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री नृसिंह रावत, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4

निर्णय

दिनांक:-08.11.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 174/2023 (2023/389) में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.04.2024 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने प्रतिवादीगण/अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेन्टस के विरुद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को दिनांक 17.10.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये। दिनांक 15.03.


राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

2024 को प्रतिवादी संख्या 1 से 03 के सम्मन तामिल होकर प्राप्त होने के बावजूद हाजिर नहीं हुए। पत्रावली वास्ते तामिली आदेश हेतु दिनांक 03.04.2024 को नियत की गई। दिनांक 03.04.2024 को प्रतिवादी संख्या 01से 03 उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा वाद पत्र पर बहस सुनी जाकर वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा बंटवारा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार, मसूदा को तहरीर जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.04.2024 से व्यथित होकर अपीलांटस ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं हुयी। उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.04.2024 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.07.2024 को हुयी अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करने लगा। तब दिनांक 12.07.2024 को अभिभाषक से सम्पर्क कर, उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर दिनांक 15.07.2024 को आदेश की प्रतिलिपि एवं तामिल नोटिस की प्रति दिनांक 19.07.2024 प्राप्त होने पर अपील माननीय न्यायालय के समक्ष जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण को कोई दोष या लापरवाही नहीं है उपरोक्त वर्णित कारण देरी सदभावी होने के कारण क्षमा किया जाना न्यायोचित है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद की जावें।



4. तत्पश्चात विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि विवादित आराजी वाकै ग्राम चावण्डिया तहसील मसूदा में स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदारी/सहकाश्तकारी की आराजीयात है। वादी बाहमी बंटवारा अनुसार काबिज चले आ रहे हैं जो वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य काफी वर्षों से बाहमी बंटवार होकर आराजी को वादी द्वारा विकसित किया गया, जो आराजी का मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा किया जाना आवश्यक है। वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य काफी वर्षों से बाहमी बंटवारा होकर आराजी खसरा नम्बर 1196 एवं 1312 को वादीगण के पक्ष में रखा गया शेष आराजी को संयुक्त रखा गया, जिसको विकसित किया गया है, इसलिए वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना चाहिए, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विश्लेषण किये, अपीलांट की तामिल प्रक्रिया एवं सुनवाई एवं साक्ष्य अभिलेख पर लिए बिना उक्त प्रकरण में उनके द्वारा तो अति संक्षिप्त तौर बिना ज्यूडिशल माईन्ड अप्लाई किये बगैर ही आक्षेपित आदेश केवल मात्र कथारा, भावनात्मक आधारों पर पारित कर दिया गया। वादी/रेस्पोजेन्ट द्वारा विवादित आराजी बाबत् पूर्व में वाद विचाराधीन होते हुए भी तथा इसकी जानकारी होते हुए भी नया पश्चात्वर्ती वाद प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्य छुपा कर नया वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून की मंशा एवं राजस्व अभिलेख के विपरीत पारित किया गया है क्योंकि प्रकरण में ना तो जवाब दावा प्राप्त किया तथा बिना तनकीवार निर्णय पारित किया गया। जो माननीय राजस्व गण्डल राज.अजमेर के द्वारा प्रतिपादित निम्न न्यायिक दृष्टांत के विपरीत है: 2016(1) आर.आर.टी.पेज 277:-राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 224- "आदेश 05 नियम 20 की बिना पालना किये प्रकरण का निर्णय किया


 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
 अजमेर

गया" तथा एक अन्य याचिक दृष्टांत 2016(2)आर.आर.टी. पेज 1147 के पैरा संख्या 04 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि " न्यायिक व्यवस्था को सुरथापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक निर्णय व आदेश आधार सहित तर्क सहित होना चाहिए, अस्पष्ट तथा संदिग्ध निर्णय अथवा नॉन स्पीकिंग आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए तथा निर्णय/आदेश स्पीकिंग होने चाहिए, साथ ही विधि द्वारा सुरथापित स्थिति है कि न्यायिक आदेश अथवा निर्णय पारित करते समय न्यायालयों को जाप्ता दीवानी के आदेश 20 नियम 04 व 05 के तहत कारण अंकित करते हुए आदेश एवं निर्णय पारित करना आज्ञापक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.04.2024 निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.04.2024 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्टस ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 गियाद अधिनियम में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये किन्तु नोटिस तामिल होने के बावजूद भी प्रतिवादीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उनको अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं थी तथा प्रार्थना-पत्र में जो प्रथम जानकारी का कारण अंकित किया गया है वह संतोषजनक नहीं है। प्रार्थीगण/अपीलांटस को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी होने के बावजूद भी अपील गियाद बाहर प्रस्तुत की है तथा देरी के जो कारण बताये गये हैं वह राद्भाविक नहीं होने से प्रार्थना-पत्र खारिज योग्य है।



6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्टस ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये जो इनके भाई मादू ने प्राप्त किये हैं इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद की जानकारी होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही अमल लाई गई है, जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 01से 03 की एक तरफा कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 04 तहसीलदार, मसूदा तथा प्रतिवादी संख्या 05 उपपंजीयक, मसूदा ने जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। वादपत्र में जवाब प्रस्तुत नहीं होने के कारण प्रकरण में तकनीयात कायम नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका पर्चा तैयार किया गया उसमें भैरु व अन्य, उपस्थित थे उनकी उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है, वह विधि सम्मत जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण कर आदेश पारित किये हैं जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस खारिज की जावें।
7. अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन सर्वप्रथम हम प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 गियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। प्रार्थीगण/अपीलांटस के द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 गियाद अधिनियम के विरुद्ध (काउन्टर में) रेस्पोंडेन्टस द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण/अपीलांटस को अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटस को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए न्यायहित में प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 गियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत


राजस्व अपील प्राधिकारी
 अजमेर

धारा 5 गियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपीलान्टस के द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर गियाद शुमार की जाती है।

8. तत्पश्चात् पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादग्रस्त आराजी बाबत् अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 02 ने रेस्पोजेन्ट संख्या 01 के विरुद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 11.10.2023 को अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, मसूदा के समक्ष पूर्व में वाद पत्र संख्या 171/2023 एवं प्रार्थना-पत्र संख्या 133/2023 पेश किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आगामी पेशी दिनांक 18.09.2024 नियत है। वादी/रेस्पोजेन्ट द्वारा विवादित आराजी बाबत् पूर्व में वाद विचाराधीन होते हुए भी तथा इसकी जानकारी होते हुए भी नया पश्चात्वर्ती वाद प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्य छुपा कर नया वाद प्रस्तुत किया है। माननीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर ने अपने न्यायिक दृष्टांत 2016(2)आर.आर.टी. पेज 1147 में यह प्रतिपादित किया है कि न्यायिक व्यवस्था का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक निर्णय व आदेश आधार सहित तर्क सहित होना चाहिए, अस्पष्ट तथा संदिग्ध निर्णय अथवा नॉन स्पीकिंग आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए तथा निर्णय/आदेश स्पीकिंग होने चाहिए, साथ ही विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्यायिक आदेश अथवा निर्णय पारित करते समय न्यायालयों को जाप्ता दीवानी के आदेश 20 नियम 04 व 05 के तहत कारण अंकित करते हुए आदेश एवं निर्णय पारित करना आज्ञापक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जाप्ता दीवानी के आदेश 20 नियम 04 व 05 की पालना किये बिना ही निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.04.2024 निरस्त किये जाने योग्य है।
9. अतः अपील अपीलान्टस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 174/2023 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.04.2024 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह इस वाद-पत्र को पूर्व में प्रस्तुत वाद पत्र के साथ सम्मिलित (कन्सोलिडेट) कर उभय पक्षकारान को जवाब का अवसर देते हुए प्रकरण में तनकीयात कायम कर तनकीयात पर साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए हिस्से अनुसार पुनःप्राथमिक डिक्री जारी की जावे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को उपस्थिति होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फौसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।



(रागचन्द्र)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रागचन्द्र)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर